

81

PBR/नगरानी/मंदसौर/भू-रू/२०१७/१९७०
न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल मोती महल ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक-

रमेश पिता कंवरलाल बलाई, आयु- 31 वर्ष
निवासी बर्डिया अमरा तह. गरोठ जिला मन्दसौर

.....आवेदक

विरुद्ध

धीरपसिंह पिता देवीसिंह सौधिया, आयु- 19 वर्ष
निवासी डिडोर परगना गरोठ जिला मन्दसौर

..... अनावेदक

R. N.

श्री राजकुमार सुब्बा
अभिजात इला
52/5/2017
30/5/2017

// आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.संहिता 1959
कार्यालय राजस्व अधीक्षक गरोठ के सीमांकन प्रकरण क्रमांक
1/अ12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2017 से परिवादत होकर
निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है //

माननीय महोदय,

रिविजन के संक्षिप्त तथ्य यह है कि :-

1. यह कि आवेदक की ग्राम बर्डिया अमरा तहसील गरोठ में भूमि स्वामित्व स्वत्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 1064 क्षेत्रफल 0.200 स्थित है।
2. यह कि उपरोक्त भूमि से लगी भूमि सर्वे नंबर 1063 क्षेत्रफल 0.620 पिता देवा बलाई के स्वामित्व की रही है।
3. यह कि अनावेदक के पिता देवीसिंह जो की आपराधिक प्रवृत्ति के होकर उदा से अपने पुत्र अनावेदक के नाम से विक्रय विलेख/विक्रय पत्र सर्वे क्रमांक 1063 क्षेत्रफल 0.620 का करवाया गया, जबकि मौके पर भूमि स्थित नहीं है, और न ही भूमि कृषि भूमि है और न ही मौके पर विक्रेता का कब्जा है, और न ही विक्रेता द्वारा विक्रय पत्र व निष्पादन के समय बिक्रित भूमि का कब्जा दिया गया है।
4. यह कि उक्त भूमि का सीमांकन अनावेदक द्वारा दिनांक 08.03.2017 को राजस्व अधिकारी से करवाया गया और उक्त सीमांकन की सूचना आवेदक और अन्य पड़ोस कृषको को नहीं दी गई, और सीमांकन में आवेदक के स्वामित्व की भूमि सर्वे नंबर 1064 रकबा 0.200 जिस पर आवेदक का बाड़ा व दीवाल बनी हुई है व बागड़ ल हुई है व 100 वर्ष पुराना पीपल का पेड़ बाप दादा का लगाया हुआ स्थित है, जिसे अनावेदक की भूमि सर्वे नंबर 1063 की सीमा बताई गई है, जिससे उत्पीडित हो रिविजन प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है -

227-228

16-6-17


3

(8)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/1970

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> <p style="text-align: left;">(3)</p>	